पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख–पत्र

वर्ष 18, अंक 3/2017

सड़क निर्माण में पीछे, सड़क हादसों में आगे हैं हम

हमारा देश विश्व में सड़क निर्माण और वाहन पंजीयन में काफी पिछड़ा है लेकिन सड़क हादसों और इसमें मरने वालों व घायलों की संख्या में हम सबसे ऊपर हैं। इसमें राजस्थान के हालात तो और भी ज्यादा खराब हैं। ऐसे में सड़क सुरक्षा पर बेहद गंभीरता व प्राथमिकता से काम करने की जरूरत है। 'कट्स' की ओर से जयपुर में 12 सितम्बर को सांसदों और मीडिया प्रतिनिधियों के बीच आयोजित विचार–विमर्श कार्यशाला में यह तथ्य खासतौर से उभर कर सामने आया।

कार्यशाला में दौसा सांसद हरीश चंद्र मीणा ने तेजी से बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं, मीडिया और आम लोग इस मसले को प्राथमिकता से लें और सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम की दिशा में सामूहिक रूप से प्रयास करें।

उन्होंने कहा कि पिछले तीन दशकों के दौरान सड़क सुरक्षा का परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है, लिहाजा लोगों को अब सड़क सुरक्षा के प्रति ज्यादा संवेदनशील, शिक्षित और जागरूक करने की जरूरत है।

चूरू सांसद राहुल कस्वा ने कहा कि सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों में बजट की कमी होती है। इस कमी को दूर किया जाना

चाहिए। इसके लिए वाहन चालकों के चालान आदि से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग सड़क सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों में किया जाना चाहिए। उन्होंने देश में अधिक संख्या में ड्राइविंग इंस्टीट्यूट खोलने और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के काम में ज्यादा सख्ती बरतने, स्कूली पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा को शामिल करने जैसे कई सुझाव दिए।

कार्यशाला में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक–2017 की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा में पारित इस विधेयक में 88 नये प्रावधान जोड़े गए हैं। इनमें 25 से ज्यादा प्रावधान सड़क सुरक्षा से संबंधित हैं।

विधेयक में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक नेशनल रजिस्टर बनाने के साथ ही लाइसेंस को पूरी तरह ऑटोमेटिक बनाने का प्रावधान भी है। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का मकसद मीडिया प्रतिनिधियों के बीच विचार–विमर्श कर सड़क सुरक्षा विधेयक, 2017 के बारे में संसदीय स्थायी समिति (पीएससी) से जुड़े सांसदों के अनुभवों को सामने लाना है।

'कट्स' के सीनियर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मधुसूदन शर्मा व ग्लोबल हैल्थ एडवोकेसी इनक्यूवेटर नई दिल्ली के कंसलटेंट नलिन सिन्हा ने सड़क हादसों में बच्चों की बढ़ती मौतों पर खास चिंता जाहिर की। शर्मा ने पूरे देश व खासकर राजस्थान में हुए सड़क हादसों के विभिन्न आंकड़ों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वर्ष 2016 में राजस्थान में 10,456 लोगों ने सड़क हादसों में जान गंवाई। पिछले दस साल में जयपुर में 4892 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई। इस अवधि में पूरे राजस्थान में सड़क हादसों से 94 हजार 489 लोग काल कवलित हुए।

हादसों के लिहाज से प्रदेश देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में डेढ़ लाख लोगों ने वर्ष 2016 के दौरान सड़क हादसे में जान गंवाई। उन्होंने बताया कि लोकसभा में यह विधेयक पारित हो चुका है और अब शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में पारित होने की उम्मीद जताई गई है।

इस अंक में...

- अफसरों ने नहीं दिया संपत्ति का ब्योरा 3
- भ्रष्ट अफसरों को बचा रही सरकार 5
- जीएसटी से आर्थिक सुधार की शुरुआत 7
- चार मीटर नीचे खिसका पानी 9
- तीन तलाक से आजाद हुई हमारी बेटियां 10

महिलाएं वित्तीय रूप से सक्षम बनें!

गरीब और कमजोर वर्ग की ग्रामीण महिलाएं वित्तीय रूप से साक्षर और समर्थ हों और आत्मनिर्भर बन सकें, इसके लिए उन्हें तकनीकी रूप से सक्षम करने की आवश्यकता है।

यह विचार 'कट्स' द्वारा भारत सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलात मंत्रालय के सहयोग से संचालित वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण परियोजना के तहत चित्तौड़गढ़ में आयोजित परियोजना शुभारंभ बैठक में बेंगू विधायक सुरेश धाकड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए।

विशिष्ठ अतिथि के रूप में चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के सभापति सुशील शर्मा ने खेतीहर महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम करने पर बल दिया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर नारायण सिंह चारण ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से बैंक लेन-देन की प्रक्रिया को समझ कर उपयोग में लाना चाहिए।

खाद्य एवं उपभोक्ता मामलात विभाग के उपनिदेशक संजय झाला ने कहा कि महिलाएं अपनी बचत का सही निवेश कर ज्यादा लाभान्वित हो सकती हैं। बैठक के प्रारंभ में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने 'कट्स' द्वारा हाल ही किए गए बेसलाइन सर्वेक्षण का हवाला देते हुए बताया कि ज्यादातर ग्रामीण महिलाएं सरकार द्वारा घोषित वित्तीय सहायता योजनाओं के बारे में नहीं जानती। उन्होंने कहा महिलाओं को वित्तीय सेवाओं से जोड़ने के प्रयास किए जाने चाहिए। 'कट्स' के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने कार्यक्रम के तकनीकी सत्र को संचालित किया।

सड़क सुरक्षा नियमों की हो पालना

मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2017 पर जागरूकता के लिए 'कट्स' एवं ऑक्सफोर्ड शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान की ओर से कोटा में कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रमोद कुमार सिंघल, सहायक कलेक्टर ने कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति नागरिकों को जागृत करना जरूरी है। सभी लोग यदि सड़क सुरक्षा के नियमों का पूरी तरह पालन करें तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है।

कार्यक्रम के प्रारंभ में 'कट्स' के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने विधेयक की खासियतों एवं भारत के सड़क सुरक्षा परिदृश्य पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में राज्य सरकार के विधिक सलाहकार भुवनेश शर्मा ने विधेयक की जानकारी देते हुए कहा कि कानून समाज की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, उनकी पालना आवश्यक है।

विधिक विभाग के एडवोकेट परमेश्वर दाधीच ने कहा कि सड़क सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है कि जरा सी चूक हो जाए तो जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में भी सड़क सुरक्षा से जुड़े कई संभागियों ने अपने विचार रखे।

प्रोओर्गेनिक को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की ग्राम स्तरीय जागरूकता कार्यशालाएं

प्रोओर्गेनिक-II परियोजना के तहत माह जुलाई से सितम्बर तक 'कट्स' द्वारा परियोजना क्षेत्र के दस जिलों में कुल 56 ग्राम स्तरीय जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। कार्यशालाओं का मुख्य उद्देश्य किसानों और उपभोक्ताओं में जैविक खेती एवं जैविक पदार्थों के उपभोग के प्रति जागरूकता बढाना था।

इन कार्यशालाओं में कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा प्रतिभागियों को जैविक खेती के विभिन्न पहलुओं के बारे में अवगत करवाया गया एवं तकनीकी जानकारी दी गई, साथ ही साथ, उपभोक्ताओं को जैविक पदार्थों के उपभोग के बारे में भी जागरूक किया गया। इन कार्यशालाओं को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रगतिशील किसान, महिलाएं एवं अन्य उपभोक्ताओं ने बढ-चढ कर हिस्सा लिया। इन कार्यशालाओं में कुल 3128 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें 1252 महिलाओं की भागीदारी रही।

पड़े रहे मिट्टी के नमूने, बंट गए कार्ड

उचित उर्वरक का इस्तेमाल सुनिश्चित कर लागत घटाने के लिए शुरु की गई केंद्र सरकार की सॉइल हेल्थ कार्ड योजना को निचले स्तर पर सरकारी मशीनरी बट्टा लगा रही है।

केंद्र के थिंक टैंक नीति आयोग ने इस योजना का अध्ययन करने के बाद जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें खुलासा किया गया है कि कई जांच लैबोरेटरी में मिट्टी के नमूने ट्रकों के बाहर ही पड़े रह गए और अंदर बिना कोई जांच किए सॉइल हेल्थ कार्ड जारी कर दिए गए। इतना ही नहीं, कार्ड तैयार करने का काम बाहरी एजेंसियों को दे दिया गया जहां गैरतकनीकी लोग मिट्टी की जांच कर कार्ड बना देते हैं। नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी गई है। *(रा.प., 27.07.17)*

विधायक कोष से बना भैंसों का तबेला

अलवर जिले में ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक की ओर से विधायक कोष के पैसे से मावड़ी गांव निवासी रिश्तेदार बालकिशन जाटव के घर के चारों तरफ व भैंसों के तबेले तक में इन्टरलॉकिंग टाइल्स लगवा दी गईं। इसमें करीब तीन लाख रुपए खर्च किए गए हैं।

आनन-फानन में केवल दो माह में काम पूरा कर ठेकेदार को भुगतान भी कर दिया गया। विधायक कोष की राशि के दुरुपयोग का यह खुलासा मीडिया ने किया था। अब प्रदेश के लोकायुक्त न्यायाधिपति एस.एस. कोठारी ने मामले पर प्रसंज्ञान लेकर जिला कलेक्टर को तलब किया है। *(दै.न., 31.08.17)*

ई-पंचायत पर अभी भी कछुआ चाल

पंचायतीराज इकाईयों में हर जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में ई-पंचायत वेब एप्लीकेशन से जोड़ने का मामला अभी भी राजनीतिक दबाव में नजर आ रहा है।

राज्य सरकार ने सरपंचों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दबाव में पारदर्शिता के इस कदम को सितम्बर-अक्टूबर महीने तक आगे सरका दिया है। इससे पहले होने वाली तैयारियां भी कछुआ चाल से आगे बढ़ रही हैं।

कहा जा रहा है कि ई-पंचायत वेब एप्लीकेशन से जोड़ने पर टेंडर और खर्च के हिसाब में पारदर्शिता होने से ज्यादातर भ्रष्ट जनप्रतिनिधि घबराए हुए हैं। इससे कमीशन और घपले की गुंजाइश कम होने से सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। *(दै.न., 18.07.17)*

कुत्तों ने काटा... मगर कागजों में

उदयपुर संभाग के भदेसर ब्लॉक मंडफिया, चित्तौड़गढ़ में स्वास्थ्य विभाग के 58 कर्मचारियों को कुत्तों ने काट लिया...। बात पर यकीन नहीं होता। लेकिन उनके नाम पर फर्जी मेडिकल बिलों का भुगतान लेने वालों ने इसे पास भी करवा लिया।

यह खुलासा स्वास्थ्य विभाग के आंतरिक जांच दल की तफ्तीश में हुआ है। इस ब्लॉक में 115 अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम पर 10 लाख रुपए के फर्जी मेडिकल बिल का भुगतान उठा लिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि रिकार्ड के मुताबिक 58 कर्मचारियों के नाम पर उठाए गए बिल रेबीज बीमारी के महंगे इंजेक्शन और दवाओं के हैं, जो कुत्ते के काटने से होती है।

(दै.भा., 10.08.17)

वसूले 400 करोड़, पर हरियाली नदारद

परिवहन विभाग ने प्रदेश में रोड टैक्स के अलावा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के मालिकों से ग्रीन टैक्स के तौर पर करोड़ों रुपए वसूले लेकिन न प्रदूषण घटाने के काम किए और न ही हरियाली बढ़ाने के प्रयास किए गए।

प्रदेश में दोपहिया व चौपहिया वाहनों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। यह जन स्वास्थ्य के लिए घातक धुआं उगल रहे हैं। इससे बढ़ रहा प्रदूषण जनता और प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन इसे घटाने या हरियाली बढ़ाने का काम नहीं हो रहा। इस काम के लिए वसूली कई 400 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि खर्च ही नहीं की गई। बल्कि बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है।

(रा.प., 20.08.17)

निःशुल्क दवा योजना में लगा रोग

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को एक ऐसा रोग लगा है, जिसे चिकित्सा महकमा पकड़ ही नहीं पा रहा। आपूर्तिकर्ता एजेंसी राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन का दावा है कि योजना के लिए वह पूरी दवाएं भेज रहा है। जबकि अस्पतालों का कहना है कि दवाएं आधी अधूरी मिल रही हैं।

सरकारी अस्पतालों में यहां तक सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल तक में मरीजों को आधी दवाएं थमाकर शेष दवाओं के लिए बाजार का रास्ता दिखाया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब दवाएं पूरी भेजी जा रही है तो मरीजों को आधी ही क्यों मिल रही हैं। मरीजों का कहना है कि जब हर हाल में देनी है दवा, तो अनुपलब्धता का ठप्पा क्यों?

(रा.प., 05.08.17, 06.08.17)

अफसरों ने नहीं दिया संपत्ति का ब्योरा

नौकरशाह भी अब मंत्री और नेताओं की राह पर निकल पड़े हैं। संपत्ति का ब्योरा देने से कतराने के मामले में वे भी नेताओं से पीछे नहीं हैं। हालांकि सरकार बार-बार अधिकारियों के लिए निर्देश जारी करती रही है कि संपत्ति और देनदारी की घोषणा तय समय पर की जाए। इसके बावजूद 400 आईएएस अधिकारियों ने अपनी संपत्तियों की जानकारी अभी तक नहीं दी है। जबकि 31 जनवरी 2017 तक उन्हें पिछले साल की यह जानकारी ऑनलाइन दे देनी चाहिए थी। लेकिन हर साल की तरह वे अपनी संपत्ति का ब्योरा देने में आनाकानी कर रहे हैं।

गौरतलब यह भी है कि हर साल 31 अगस्त तक केन्द्र के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्रियों को सांसदों, विधायकों और मंत्रियों द्वारा अपनी संपत्ति और देनदारी का ब्योरा देना होता है। लेकिन ज्यादातर अपने इन दायित्वों को भूल जाते हैं और समय पर ब्योरा नहीं देते।

(रा.प., 18.09.17)

कारोबार कैसे कर सकते हैं सांसद...!

सांसद और विधायक जनप्रतिनिधि रहते हुए कोई दूसरा कारोबार कैसे कर सकते हैं। सांसदों और विधायकों की आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणी की है।

एनजीओ लोक प्रहरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांसद और विधायक यह बता भी दें कि उनकी आय में इतनी तेजी से बढ़ोतरी बिजनेस करके हुई है, तो सवाल उठता है कि सांसद और विधायक होते हुए आप कोई भी बिजनेस कैसे कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने घोषित आय से अधिक संपत्ति वाले 7 सांसदों व 98 विधायकों के नाम वाला सीलबंद लिफाफा भी खोला लेकिन अभी उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए। *(रा.प., 13.09.17)*

नेताओं की संपत्ति बढ़ी कोर्ट ने ली खबर

चुनाव खर्च के ब्योरे का आंकडा न होने की दलील पर चुनाव आयोग को फटकार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की खिंचाई की है। जस्टिस जे.चेलमेश्वर और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर की बेंच ने केंद्र सरकार से कहा है कि उन सांसदों और विधायकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई जिनकी संपत्ति 5 साल में 500 प्रतिशत तक चुनाव हलफनामा भरने के बाद अचानक बढ़ गई।

सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ लोक प्रहरी की याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को यह जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। याचिका में अनुरोध किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव सुधारों को लेकर आदेश दे कि नामांकन के समय प्रत्याशी अपनी और परिवार की आय के स्रोत का खुलासा करे। *(रा.प.एवं दै.भा., 07.09.17)*

करोड़ों खर्च...फिर भी घट गए जंगल

राजस्थान में प्लांटेशन के नाम पर हर साल 200 से 300 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया जाता है। पौधे लगाने के लिए उस बजट को खर्च भी किया जाता है। हजारों हेक्टेयर वन भूमि पर प्लांटेशन करने और उनके जीवित रहने का दावा भी किया जाता है। लेकिन जब देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वे की रिपोर्ट देखते हैं तो वन विभाग के सभी दावे हवा हो जाते हैं।

पिछले पांच सालों की पड़ताल में सामने आया कि जंगल बढ़ाने के नाम पर 1200 से 1500 करोड़ रुपए के बीच खर्च किया गया तथा 3258 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पौधे लगाए गए। इसके बावजूद इस अवधि में 61 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कम हो गया। वन मंत्री राजेन्द्र सिंह खिंवसर तक प्लांटेशन की इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं।

(दै.भा., 12.07.17)

गरीबों के गेहूं की हो रही कालाबाजारी

प्रदेश में राशन की दुकानों पर गरीबों को वितरित होने वाले गेहूं की कालाबाजारी रोकने के लिए पोस मशीन लागू होने और सारा सिस्टम ऑनलाइन होने के बावजूद एक साल में 900 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का गेहूं कालाबाजारी की भेंट चढ़ गया। जो लोग गेहूं लेने नहीं आ रहे थे, उनके हिस्से के 50 हजार मीट्रिक टन गेहूं का खाद्य विभाग के पास कोई हिसाब तक नहीं है।

राशन की दुकानों पर मिलने वाले 2 रुपए प्रति किलो के गेहूं को अगर बाजार में 15 रुपए प्रति किलो की दर से भी बेचा जाए तो हर महीने 75 करोड़ और हर साल 900 करोड़ रुपए कमा लिए जाते हैं। इतना ही नहीं हर महीने सवा तीन लाख राशनकार्डधारी गेहूं नहीं लेते हैं। जबकि उनके हिस्से का गेहूं हर महीने जारी किया जाता है। *(दै.भा., 27.08.17)*

शिक्षा का अधिकारः अपने हाल पर

शिक्षा का अधिकार (आरटीआई) कानून बनने के बाद केंद्र ने इस योजना को अपने हाल पर छोड़ दिया। हर साल केंद्र से फंड मांगने वाले राज्यों ने कानून बनने के बाद छह सालों में 87,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए। इस तथ्य का खुलासा संसद में प्रस्तुत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए जिम्मेदार राज्य सरकार या संस्थाओं ने लगातार लापरवाही बरती है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010-11 से 2015-16 के बीच फंड के इस्तेमाल में 21 से 41 फीसदी तक की कमी दर्ज की गई है। आरटीई में प्रावधान है कि छह वर्ष से 14 साल तक के सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, जिससे पता लगाया जा सके कि इस समूह के सभी बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं या नहीं। *(रा.प., 23.07.17)*

बेरोजगारी पर आंकड़े सही नहीं!

सरकार की नौकरी बढ़ाने वाली योजनाओं के दावों के बावजूद पिछले तीन सालों में बेरोजगारी बढ़ी है। आंकड़ों के अनुसार देश में बेरोजगारी वर्ष 2013-14 में 4.9 फीसदी से 2015-16 तक 5 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। सरकार के कई सर्वेक्षणों में नौकरी घटने की बात ही सामने आ रही है।

अब नीति आयोग ने इन आंकड़ों पर ही सवाल उठा दिया है। आयोग की साइट पर अपलोड एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में रोजगार से जुड़े सभी आंकड़े या तो बहुत पुराने हैं या गलत तरीके से इकट्ठे किए गए हैं। रिपोर्ट में पुराने सभी आंकड़ों को गलत बताते हुए कहा गया है कि ये सभी आंकड़े भ्रमित करने वाले हैं। *(रा.प., 16.07.17)*

याद आने लगे पंचायत भवन

चुनाव नजदीक आते ही सरकार को पंचायत समिति के भवनों के निर्माण की फिर से याद आने लगी है। गौरतलब है कि ढ़ाई साल पहले पंचायतीराज संस्थाओं के पुनर्गठन का काम शुरू हुआ था। मौजूदा सरकार ने नवम्बर, 2014 में 47 नई पंचायत समितियां बनाई थीं।

सरकार ने वर्ष 2015-16 के बजट में नई पंचायत समितियों के भवन निर्माण की घोषणा भी की, लेकिन पिछले ढ़ाई साल से यह ठंडे बस्ते में बंद थीं। भवनों के लिए जमीन तक आवंटित नहीं हुई। *(रा.प., 14.08.17)*

सरकार ने वादा नहीं निभाया–अन्ना

समाजसेवी अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चार पेज की चिट्ठी लिखकर भ्रष्टाचार के खिलाफ फिर से आंदोलन करने का फैसला लिया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि छह साल बाद भी भ्रष्टाचार को रोकने वाले एक भी कानून पर अमल नहीं हो पाया।

लोकपाल, लोकायुक्त की नियुक्ति करने और भ्रष्टाचार को रोकने वाले सभी सशक्त बिलों पर सरकार सुस्ती दिखा रही है। दिसंबर 2013 में दोनों सदनों में लोकपाल बिल पारित होने के बावजूद केंद्र सरकार ने इसे अभी तक लागू नहीं किया। कानून पारित होने को चार साल होने को आए लेकिन अभी तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अब मजबूरन उन्हें फिर से आंदोलन छेड़ना पड़ेगा।

(दै.भा., 31.08.17 एवं रा.प., 01.09.17)

राजनीतिक चन्दे की तय होगी सीमा

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार शीघ्र ही एक प्रमुख निर्णय की घोषणा करेगी। जिसके माध्यम से राजनीति में आने वाले कालेधन को रोका जाएगा। अधिकांश राजनैतिक खर्च हिसाब–किताब से बाहर होते हैं। पार्टियों के नकद चन्दे पर सीमा लगाई जानी चाहिए।

यह संकेत जेटली ने एसबीआई बैंकिंग एण्ड इकोनोमिक सम्मेलन को मुम्बई में वीडियो के माध्यम से संबोधित करते हुए दिए हैं। उन्होंने कहा कि गत 70 वर्ष में विश्व की सबसे बड़ी लोकतान्त्रिक व्यवस्था चन्दे पर आश्रित रही है। इस व्यवस्था में सुधार जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी यह चाहते हैं। सरकार अब इस कार्य पर प्राथमिकता से ध्यान देगी। *(न.नु., 14.07.17)*

भ्रष्ट अफसरों को बचा रही सरकार

भ्रष्टाचार के मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं, वहीं केन्द्र व राजस्थान में भाजपा की सरकार होने के बावजूद भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे अफसरों पर कार्रवाई में लगातार देरी हो रही है। करोड़ों रुपए के घोटाले और रिश्वतकांड में फंसे करीब 23 अफसरों पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति देने में सरकार आनाकानी कर रही है। इससे दर्ज प्रकरण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इन अफसरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर अभियोजन चलाने की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। कई मामलों में राज्य सरकार ने सहमति जताते हुए केंद्र को स्वीकृति जारी करने को प्रस्ताव भी भेज रखे हैं लेकिन काफी समय गुजरने के बावजूद केंद्र ने अब तक निर्णय नहीं दिया।

(रा.प., 22.07.17)

नौकरशाही को कसने की तैयारी...

नौकरशाही को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने नई तैयारी की है। अब भ्रष्ट आईएएस–आईपीएस अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने हर मंत्रालय के सतर्कता विभाग से कहा है कि वे भ्रष्ट अधिकारियों के दस्तावेज तैयार करें। यह सूची सीबीआई और सीबीसी को भी भेजी जाएगी।

यह दोनों ही जांच एजेंसियां सूची में शामिल अफसरों की निगरानी रखेंगी। भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जरूरी कार्रवाई करेगी या फिर जरूरत पड़ने पर जुर्माना, नौकरी में डिमोशन या सेवा से बर्खास्तगी सहित विभागीय कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगी। इसके बाद अफसरों को दंड़ित किया जाएगा।

(रा.प., 01.08.17)

जानकारी देने में आनाकानी

केन्द्र सरकार के नौकरशाह आरटीआई के जरिए मांगी जा रही घोटालों की जानकारियां नहीं दे रहे हैं। वे इन शिकायतों को भी थर्ड पार्टी इनफॉर्मेशन घोषित कर रहे हैं, जिनमें सबूतों समेत घोटालों संबंधी जानकारियां है। यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी भी इसे गंभीरता से लेने की अपेक्षा आवेदकों तथा अपीलार्थियों को जवाब भेज रहे हैं कि वे संबंधित मंत्रालय व कार्यालयों से सूचना प्राप्त करें।

ताजा मामला उस मृदा परीक्षण घोटाले का है, जिसके जरिए प्रधानमंत्री ने देश के खेतों का स्वास्थ्य ठीक करने का अभियान छेड़ा हुआ है, लेकिन कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने आरटीआई आवेदन का जवाब तक नहीं दिया। *(रा.प., 23.08.17)*

भ्रष्टाचार जांच का औचक निरीक्षण

भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को औचक निरीक्षण करने को कहा है। दरअसल, केंद्रीय सतर्कता आयोग की हाल ही नयी सतर्कता नियम पुस्तिका जारी हुई इसमें कहा गया है कि सीबीआई संबंधित विभाग की सतर्कता इकाई के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के स्थानों पर औचक निरीक्षण कर सकती है।

नए दिशा–निर्देशों के मुताबिक निलंबन पर चल रहे अधिकारियों अथवा सेवानिवृत्ति के करीब पहुंचे अधिकारियों पर लगे आरोपों की जांच को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सतर्कता मामलों पर तैयार नये दिशा–निर्देशों में यह कहा गया है। इसमें ऐसे मामलों पर जांच–पड़ताल को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया गया है। *(न.नु., 09.09.17)*

कालेधन के ढेर पर बैठी हैं सभी राजनीतिक पार्टियां

वर्षों से कालेधन को अर्थव्यवस्था के लिए घातक बताने वाली भारत की राजनीतिक पार्टियां स्वयं कालेधन पर बैठी हैं। वे पारदर्शिता का अलाप तो खींचती हैं, लेकिन मौका आने पर उससे बचकर निकलने का काई मौका नहीं छोड़तीं। राजनीतिक दलों का यह विचित्र चरित्र अनेक अवसरों पर रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है।

केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा शपथपत्र दिया गया है जिसमें राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाया जाना अनिवार्य बनाया गया था।

इतना ही नहीं राजनीतिक दलों के चन्दे को पारदर्शी बनाने के रास्ते को भी बंद करने के लिए संसद में कानून भी पारित करा लिया गया। किसी भी दल ने इस कानून का विरोध तक नहीं किया। इससे साबित है कि सभी अंदरखाने में एक हैं। *(रा.प., 21.08.17)*

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के 60% ट्रैप सोम-शुक्र को

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के पिछले डेढ़ साल के आंकड़े बताते है कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ने में एसीबी के लिए सोमवार और शुक्रवार के दिन सबसे शुभ रहे हैं। एसीबी की ट्रैप की 60 फीसदी कार्रवाई इन्हीं दो दिनों को हो रही है। पिछले डेढ़ साल में हुई ट्रैप की कार्रवाइयों को देखा जाए तो इस अवधि में किए गए 70 ट्रैप में 40 केवल सोमवार और शुक्रवार को किए गए। इनके अलावा 30 कार्रवाई किसी अन्य सार्वजनिक अवकाश के बाद हुई और एक कार्रवाई रविवार को हुई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अवकाश के ठीक पहले और बाद का दिन ट्रैप के लिए सबसे मुनासिब साबित हो रहा है।

एसीबी ने 2016 में 21 प्रमुख ट्रैप किए। इसमें से 6 सोमवार को और 11 शुक्रवार को किए गए। इस साल मई तक ट्रैप की कुल 49 कार्रवाई की गई इनमें से 10 सोमवार और 13 शुक्रवार को हुई। अन्य कार्रवाई किसी न किसी सार्वजनिक अवकाश के ठीक पहले या बाद में हुई। लेकिन वी.के सिंह, आईजी, एसीबी इसे संयोग की बात मानते हैं। *(दै.भा., 10.08.17)*

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
दौसा	कन्हैयालाल रैगर	प्रवर्तन अधिकारी, रसद विभाग	47,000	*दै.न., 07.07.17*
बाड़मेर	गुमान सिंह राजपुरोहित	पर्यवेक्षक, सेंट्रल कॉ-आपरेटिब बैंक, कल्याणपुर	10,000	*दै.भा. एवं दै.न., 11.07.17*
कोटा	प्रीति सेन सुरेश कुमार	जेईएन, जल ग्रहण विभाग, जिला परिषद ग्राम सचिव, जिला परिषद, कोटा	25,000 18,000	*दै.न. एवं रा.प., 13.07.17*
जयपुर	बसन्त कुमार	सरपंच, महारकला ग्राम पंचायत, चौमूं	25,000	*दै.भा., 21.07.17*
जयपुर	कैलाश चंद मीणा	उप-तहसीलदार, गोविन्दगढ़ पंचायत समिति	50,000	*रा.प. एवं दै.न., 26.07.17*
झालावाड़	लेखराज शर्मा	तकनीकी सहायक, पंचायत समिति, अकलेरा	15,000	*रा.प. एवं दै.न., 29.07.17*
जालौर	त्रिकमदान चारण	आयुक्त, नगर परिषद, जालौर	50,000	*रा.प. एवं दै.भा., 31.07.17*
बारां	ओम प्रकाश सोनी	आबकारी सीआई, आबकारी विभाग, बारां	10,000	*दै.भा., 01.08.17*
बारां	गोपाल लाल गुर्जर	एसआई, शहर कोतवाली, बारां	20,000	*रा.प. एवं दै.भा., 03.08.17*
जयपुर	दीपक योगी	जेईएन, जयपुर विकास प्राधिकरण (जोन-12)	50,000	*दै.भा. एवं रा.प., 09.08.17*
जयपुर	रमेश चंद अग्रवाल पुरुषोत्तम	उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण (जोन-3) दलाल	60,000	*दै.भा. एवं दै.न., 10.08.17*
उदयपुर	बहादुर सिंह	एएसआई, चीतरी थाना, उदयपुर	19,000	*दै.भा., 12.08.17*
हनुमानगढ़	मोहन सिंह गोदारा	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भादरा	20,000	*रा.प., 12.08.17*
जयपुर	होशियार सिंह	थाना प्रभारी, लक्ष्मणगढ़ थाना	1,50,000	*दै.भा., 19.08.17*
बीकानेर	प्रकाश चंद प्रजापत	जेईएन, जोधपुर डिस्काम, देशनोक	15,000	*रा.प. एवं दै.भा., 25.08.17*
श्रीगंगानगर	बच्चन सिंह	पुलिस उपनिरीक्षक, नई मण्डी थाना, घड़साना	25,000	*दै.न., 14.09.17*
जयपुर	सागर मल रामधन पूनिया	सब इंस्पेक्टर, झोटवाड़ा थाना, जयपुर दलाल, सीएलजी सदस्य, कालवाड़ थाना, जयपुर	60,000	*रा.प. एवं दै.भा., 16.09.17*
पाली	केसा राम मुकेश कुमार	पार्षद, तखतगढ़ नगर पालिका, वार्ड-16 पार्षद, तखतगढ़ नगर पालिका, वार्ड-15	1,50,000 1,50,000	*रा.प. एवं दै.न., 22.09.17*
जयपुर	महावीर प्रसाद चोटिया	प्रोवेशनल आरपीएस, (पूर्व में गोविन्दगढ़ सर्किल में)	1,10,000	*रा.प., 26.09.17*
करौली	रामचंद्र मीणा लल्लूलाल गुर्जर	उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन सिटी रामचन्द्र मीणा के रीडर	80,000	*रा.प. एवं दै.न., 30.09.17*

किसान खुदकुशी, मुआवजा हल नहीं

उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार से कहा है कि किसान की आत्महत्या के बाद मुआवजा देना समस्या का हल नहीं है। सरकार को किसानों के कर्ज के असर को कम करना चाहिए।

सरकार को चाहिए कि किसानों के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उनके सही क्रियान्वयन के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास करें। फसल बर्बाद होने पर किसानों से ऋण वसूली में नरमी बरती जाए।

जनहित याचिका की सुनवाई पर चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बैंच ने सरकार को उक्त निर्देश दिए। बैंच ने सरकार की इस बात पर भी सहमति जताई कि किसान कल्याण योजनाओं के नतीजे सामने आने के लिए एक साल का वक्त दिया जाए।

(रा.प. एवं दै.भा., 07.07.17)

गरीबों को मिलता रहेगा गेहूं व चावल

सरकार ने लोकसभा में कहा है कि अगले साल तक गरीबों को दो रुपए किलो गेहूं व तीन रुपए किलो चावल दिया जाता रहेगा। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो देश की 81 करोड़ जनता को दो रुपए प्रति किलो गेहूं और तीन रुपए प्रति किलो चावल देता है।

उन्होंने कहा कि इस योजना को तीन साल हो गए हैं और हमने फैसला लिया है कि जून, 2018 तक इसी दाम पर खाद्यान्न देते रहेंगे। इस दिशा में केंद्र सरकार अपना काम कर रही है और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्यों की है कि कोई भूखा नहीं रहे।

(न.नु., 02.08.17)

घट रही है भूमि की उर्वरा शक्ति

राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण की रिपोर्ट एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो ने राजस्थान की समस्त जमीन का लैंडसेट इमेजरी के जरिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया है।

यह सर्वे सबसे ज्यादा प्रमाणित माना जाता है। इसमें सामने आया है कि मिट्टी के पोषक तत्वों में लगातार कमी आ रही है। रासायनिक खाद-बीज के अंधाधुंध उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति घट रही है।

सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बेतरतीब रासायनिक खाद और बीजों के उपयोग को रोका जाए। मिट्टी की जांच के बाद ही आवश्यक समुचित मात्रा में उर्वरकों को उपयोग में लिया जाए। *(रा.प., 02.07.17)*

सिंचाई व भंडारण को प्राथमिकता

केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए कई क्षेत्रों में एक साथ काम कर रही है। सबसे पहले सिंचाई और भंडारण व्यवस्था को बेहतर करने के कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए बजट को बढ़ाया गया है।

उन्होंने बताया कि कृषि बाजार में किए जा रहे सुधारों से आढ़तियों का दबदबा खत्म होगा और किसानों को फसल की वाजिब कीमत मिल सकेगी। हमारा प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन पर खास ध्यान है। इसके साथ ही बागवानी, पशु पालन जैसे कृषि से जुड़े कई क्षेत्रों पर भी जोर दिया जा रहा है।

(रा.प., 11.09.17)

किसानों का 50 हजार तक कर्ज माफ

प्रदेशभर के किसानों के 50 हजार रुपए तक के कर्ज माफ किए जा सकेंगे। इसके लिए सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा।

यह कमेटी अन्य राज्यों में किसान कर्ज माफी का अध्ययन कर एक माह में रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट के आधार पर कर्ज माफी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सरकार व आंदोलन कर रहे किसानों के बीच यह सहमति बनी है।

यह जानकारी कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने देते हुए कहा कि इससे राज्य सरकार पर तकरीबन 20 हजार करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। गौरतलब है कि राजस्थान में आजादी के बाद पहली बार किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। *(रा.प. एवं दै.न., 14.09.17)*

पेंशन योजनाओं में आएगा बदलाव

सरकार सामाजिक पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए नेशनल सोश्यल असिस्टेंट प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। सरकार जरूरतमदों को दी जा रही वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन आदि में इजाफा करेगी।

बदलावों के बाद सरकार को इसके लिए करीब 22 हजार करोड़ रुपए का अलग से फंड जुटाना पड़ेगा। इसके लिए जीएसटी से प्राप्त राशि में से फंड बनाने के साथ ही फंडिंग में भी बदलाव करने पर विचार चल रहा है। केन्द्र सरकार सारा खर्च खुद उठाने के बजाय 40 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार से जुटा सकती है। *(रा.प., 07.09.17)*

जीएसटी से आर्थिक सुधार की शुरुआत

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि जीएसटी देश-प्रदेश की उन्नति में मील का पत्थर साबित होगा। यह आर्थिक सुधार की दिशा में उठाया गया कदम है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस निर्णय के बाद माल और सेवाओं पर देशभर के करों में समानता आ जाएगी। इससे व्यापार करना आसान होने जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू करने से पहले केन्द्र सरकार ने आम आदमी का विशेष ध्यान रखा है। अनाज को कर मुक्त व दैनिक उपयोग की जरूरी वस्तुओं पर टैक्स मौजूदा कर भार से कम रखा गया है। जीएसटी लागू करने से पहले प्रदेश में भी इसकी पूरी तैयारी की गई थी। *(दै.न., 02.07.17)*

सोलर पंप कृषि कनेक्शन योजना शुरू

प्रदेश में किसानों को लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से सोलर पंप कृषि कनेक्शन योजना शुरू की गई है। दिसम्बर 2013 तक कृषि कनेक्शन के लिए लम्बित 3 और 5 एचपी के लगभग 70 हजार आवेदकों के कृषि पंप सेटों को सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत करने व ग्रीन ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है।

योजना पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है। इस योजना से किसानों को दिन में बिजली मिलेगी और बिजली बिल भी नहीं देना पड़ेगा। योजना में पंजीकरण की जानकारी विद्युत निगम के संबंधित अभियंता (पवस) कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। *(दै.न., 07.07.17)*

बिजली बचाने में प्रदेश सबसे आगे

स्ट्रीट लाइटों में सोडियम और ट्यूबलाइट की जगह एलईडी लाइट्स बदलकर बिजली बचाने में राजस्थान देश में पहले पायदान पर आ गया है। प्रदेश के 11 शहरों में थर्ड पार्टी टेस्टिंग में 61 फीसदी तक बचत सामने आई है। इन शहरों में एलईडी के कारण एक साल में 247 लाख यूनिट बिजली बची, जिससे 19.77 करोड़ रुपए कम खर्च हुए।

अब तक प्रदेश के 153 शहरों में 7.9 लाख रोडलाइटों पर एलईडी लाइट्स लगाई जा चुकी है। सरकार का मानना है कि प्रदेश की 12.5 लाख रोडलाइटों पर एलईडी प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद 1751 लाख यूनिट्स बिजली बचेगी और हर साल करीब 140 करोड़ रुपए की बचत होगी। खेदजनक यह है कि प्रदेश की राजधानी होने के बावजूद जयपुर इस क्षेत्र में अन्य जिलों से काफी पिछड़ा हुआ है। *(दै.भा., 18.08.17)*

सौभाग्य योजना से होगा हर घर रोशन

केंद्र सरकार ने अगले सवा साल में देश के हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए 'सौभाग्य' योजना शुरू की है। इसके तहत करीब चार करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे।

अभी प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना चल रही है। इस योजना से पहले प्रदेश में करीब 18 लाख परिवार बिजली की रोशनी से वंचित थे। अनुमान है इस योजना के बाद भी करीब 10 लाख परिवार बिजली की रोशनी से वंचित रह जाएंगे। अब ऐसे परिवार भी सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन पा सकेंगे। *(दै.भा., 26.09.17 एवं रा.प., 30.09.17)*

हमारी सौर ऊर्जा से रोशन होगा देश

प्रदेश के रेगिस्तानी इलाके वाले पांच जिले सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए देश में सबसे बेहतर जगह बनने जा रहे हैं। ऐसा गुजरात के बनाकांठा से पंजाब के मोगा तक बनने वाले ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर यानी इलेक्ट्रोनिक्स कॉरिडोर बनने से होगा। यह कॉरिडोर बीकानेर सहित अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर आदि जिलों से गुजरेगा।

इलेक्ट्रोनिक्स कॉरिडोर की 8 हजार केवी की मुख्य लाइन बिछाने का काम जोरों से चल रहा है। इस पर चार सब-स्टेशन भी बनने शुरू हो गए हैं। यह कॉरिडोर अगले साल अगस्त तक बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद प्रदेश में उत्पादित सौर ऊर्जा से न केवल उत्तर भारत बल्कि पूरा देश रोशन हो सकेगा। *(रा.प., 22.08.17)*

विद्युत छीजत में लानी होगी कमी

केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि उन्हें शीघ्र ही विद्युत की चोरी रोककर बिजली छीजत को 10 प्रतिशत के स्तर पर लाने का प्रयास करना चाहिए। मंत्रालय ने यह कार्य छह माह की अवधि में पूरा करने का निर्देश दिया है।

ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक झारखण्ड, उत्तर प्रदेश व बिहार के कुछ शहरों व कस्बों में 90 प्रतिशत तक छीजत व बिजली चोरी होती है। ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही कहा था कि देश में तकनीकी व वाणिज्यिक छीजत 2016-17 में घटकर 20 प्रतिशत रह गई है। लेकिन राज्यों के कुछ शहरों व कस्बों में अभी भी बिजली छीजत काफी अधिक है। राज्यों को ऐसे शहरों व कस्बों की पहचान कर वहां इसे 10 प्रतिशत तक लाना होगा। प्रदेश का टोंक जिला भी सर्वाधिक 86.7 प्रतिशत बिजली चोरी और छीजत को लेकर बदनाम है। *(न.नु., 03.08.17)*

धरती की गर्मी से बनेगी बिजली

वर्ष 2022 तक हम धरती में मौजूद गर्मी से भी बिजली बनाने में सक्षम होंगे। केन्द्र सरकार ने अगले पांच साल में भू-तापीय ऊर्जा (जियोथर्मल) से 1,000 मेगावाट क्षमता के प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा है। इससे सालाना औसतन 830 करोड़ यूनिट बिजली पैदा होगी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इस दिशा में काम कर रहा है।

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने इसकी लागत का अनुमान भी लगा लिया है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जियोथर्मल से देशभर में 10,000 मेगावाट तक बिजली पैदा की जा सकती है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और एमएनआरई इस पर रिसर्च और डवलपमेंट कर रहा हैं। *(दै.भा., 25.09.17)*

बिजली उत्पादन क्षमता हो जाएगी पांच लाख मेगावाट

देश के बिजली क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। अगले पांच साल में उत्पादन क्षमता बढ़कर पांच लाख मेगावाट हो जाने की उम्मीद है। बिजली सचिव ए.के. भल्ला ने यह जानकारी देते हुए कहा कि साल के अंत तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य और बिजली मांग बढ़ने के कारण पारेषण एक चुनौति होगी।

उन्होंने बताया कि मौजूदा बिजली उत्पादन क्षमता 330 गीगावाट से बढ़कर 500 गीगावाट यानी पांच लाख मेगावाट हो जाने की उम्मीद है। पारेषण के क्षेत्र में कंपनियों के लिए अवसर का जिक्र करते हुए भल्ला ने कहा कि राज्यों के बीच पारेषण व्यवस्था बेहतर है। लेकिन राज्य के भीतर पारेषण एक चुनौती है। *(न.नु., 15.09.17)*

जल स्वावलंबन बना रोल मॉडल

राजस्थान में चल रहे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की देशभर में सराहना हो रही है। इस अभियान से राजस्थान अन्य प्रदेशों में रोल मॉडल बन गया है। अभियान के तहत प्रदेश में हुए जल संरक्षण संरचनाओं को अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाया जा रहा है। इस अभियान में अब तक प्रदेश के 7742 गांवों का चयन कर 2 लाख 28 हजार से भी अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिसके काफी अच्छे परिणाम सामने आए हैं।

एनजीटी की ओर से पर्यावरण पर भोपाल में क्षेत्रीय सम्मेलन के घोषणा-पत्र में यह संकल्प लिया गया है कि वहां भी जल स्वावलंबन अभियान चलाया जाएगा। वहां अभियान में कराए गए कार्य और वैज्ञानिक तकनीक का जीवंत प्रस्तुतिकरण दिया गया था।

(दै.भा., 01.08.17)

जल प्रबंधन व्यवस्था हो दुरुस्त

विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशी निवेश और प्रोद्यौगिकियों को आकर्षित करने के लिए भारत को देशभर में अपनी जल प्रबंधन व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। वर्तमान में भारत में जल प्रबंधन व्यवस्था जल संसाधन मंत्रालय से लेकर पर्यावरण मंत्रालय एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तक और केन्द्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तथा नगरीय निकायों तक बहुस्तरीय है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में जल विकास की अनंत संभावनाएं हैं।

पीने का पानी, सिंचाई व उद्योगों में पानी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। सार्वजनिक नीति पर तीसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में दिल्ली विश्वविधालय के प्राध्यापक सत्यजीत सिंह ने यह जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे में जल क्षेत्र के विकास हेतु सार्वजनिक-निजी साझेदारी को एक विकल्प के रूप में अपनाना जरूरी हो गया है। *(न.नु., 01.07.17)*

सेटेलाइट से मिली सुखद तस्वीर

सदियों से बरसात के अभाव में अकालग्रस्त जिले के रूप में पहचाना जाने वाला बाड़मेर जिले ने सुखद समाचार देने शुरू कर दिए हैं। वहां जमीन के अंदर बह रही सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र में अथाह जल भंडार मिला है। वहां कई गांवों में अब तस्वीर ही बदल गई है। एक दर्जन से भी ज्यादा गांवों में नलकूप और ट्यूबवेल खुद गए हैं। वहां अब मीठा पानी है। साल में दो बार अच्छी खेती होती है। सिंचाई के लिए भी भरपूर मात्रा में पानी आ रहा है। सेटेलाइट से ली गई तस्वीर बताती है कि सरस्वती नदी के इस पुराने मार्ग पर बसे कई गांवों में भूमिगत जल का बड़ा भंडार है।

सरस्वती की घाटी हरियाणा में कुरूक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, अनूपगढ़, राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर-बाड़मेर और फिर गुजरात में खंभात की खाड़ी तक जाती थी। *(दै.भा., 10.07.17)*

चार मीटर नीचे खिसका पानी

पूर्वोत्तर के तीन और एक तटीय राज्य को छोड़कर भारत के तमाम राज्यों में भू-जल पाताल में जा रहा है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में हालात और भी खराब है। इन तीनों जिलों में मानसून आने से पूर्व भू-जल चार मीटर तक नीचे जा चुका था। केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने कुल मिला कर हालात को चिंताजनक बताया है। हालांकि मानसूनी वर्षा से भू-जल की मामूली भरपाई होने की उम्मीद है।

केंद्रीय भू-जल बोर्ड चालू वर्ष में मानसून आने से पहले देशभर में बनाए गए 14 हजार 465 कुओं के जरिए भू-जल का आकलन किया था इनमें राजस्थान के 859 कुओं के परीक्षण के बाद पाया गया कि राज्य के इन तमाम कुओं में भू-जल चार मीटर नीचे खिसक गया है।

(रा.प., 09.09.17)

बीसलपुर बांध की बढ़ेगी ऊंचाई!

बीसलपुर बांध भरने के बाद फिजूल बहने वाले करीब 6.9 टीएमसी पानी को रोकने के लिए बांध की ऊंचाई एक आरएल मीटर बढ़ाने की योजना है। बांध में अब तक एक साल की आपूर्ति के बराबर पानी आ चुका है। बरसात जारी रहने से यह भर जाएगा। वर्तमान में बांध की ऊंचाई 315.50 आरएल मीटर है और भराव क्षमता 38.70 टीएमसी है।

जलदाय मंत्री सुरेन्द्र गोयल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ऊंचाई बढ़ाने के साथ ही रामी नदी से पानी लाने को लेकर भी 5800 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है। इस पर तेजी से काम चल रहा है।

(रा.प., 09.08.17)

पानी का कनेक्शन लेना महंगा

प्रदेश में अब पानी का कनेक्शन लेना महंगा होगा। नया कनेक्शन लेने के लिए आवेदन के साथ सहमति और करार पत्र के रूप में स्टांप पेपर लगाना अनिवार्य होगा। अर्थात अब आवेदन के साथ 550 रुपए के स्टांप पेपर पर करार और 50 रुपए के स्टांप पेपर पर सहमति पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

गुप-चुप तरीके से लागू किए गए इस फैसले का कई जगहों पर विरोध भी नजर आ रहा है। वहीं कुछ जगहों पर गत अप्रेल माह से ही स्टांप ट्यूटी की वसूली की जा रही है।

(दै.न., 15.07.17)

प्रदेश में नदियों को जोड़ा जाएगा

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि प्रदेश को जल संकट से बचाने के लिए 40 हजार करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में नदियों को जोड़ने की योजना पर कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि जल संकट को लेकर राज्य सरकार पहले से ही संवेदनशील है। जल स्वावलंबन अभियान के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा देने से प्रदेश के कई जिलों के डार्क जोन में पानी का संकट दूर हुआ है। अब नदियों को जोड़ने के लिए बनी योजना के तहत हाड़ौती की परवन, पार्वती और कालीसिंध को जोड़ा जाएगा। इससे राज्य के 13 जिले लाभान्वित होंगे। *(दै.न., 29.09.17)*

मोदी की नजर बच्चों के टीकों पर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि अगले साल के अंत तक 90 फीसदी बच्चों को सभी टीके लगने लगें। उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों की विशेष कोशिशों के बाद भी अभी तक देश में टीकाकरण का कवरेज 72 फीसदी तक ही पहुंचा है। उन्होंने निर्देश दिया है कि अभियान के दौरान इसकी डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट उन्हें भेजी जाए।

प्रधानमंत्री ने टीकाकरण की मौजूदा रफ्तार से असंतोष जताते हुए इस पर खासतौर से ध्यान देने को कहा है। अगर यह लक्ष्य हासिल हो जाता है तो भारत टीकाकरण में फिसड्डी होने का अपना एक बड़ा कलंक धो सकेगा। *(रा.प., 07.07.17)*

कुपोषण पर अंकुश लगाना जरूरी

नीति आयोग ने कुपोषण को देश के विकास में रोड़ा मानते हुए कहा है तेजी से आर्थिक विकास के लिए पोषण सुरक्षा का लक्ष्य हासिल करना जरूरी है। आयोग ने कुपोषण मुक्त भारत के लिए 'राष्ट्रीय पोषण रणनीति' पेश की है।

इसमें इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तर्ज पर राष्ट्रीय पोषण मिशन के गठन समेत व्यापक प्रस्ताव रखे गए हैं। रणनीति में दीर्घकालीन नजरिए से 2030 तक सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। *(रा.प., 11.09.17)*

अब सास-बहू से होगी सीधी बात

राजस्थान के जिन जिलों में बच्चों की तादाद प्रति परिवार ज्यादा है, उनको बच्चे कम ही अच्छे की सीख देने के लिए अब चिकित्सा विभाग जल्द ही सीधे परिवार की महिलाओं से बात करने जा रहा है। खासकर सास और बहूओं से। इसके लिए 10 सितम्बर से ऐसे जिलों के 16250 गांवों में सास-बहू सम्मेलनों का आयोजन होगा।

यह जानकारी चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव वीनू गुप्ता ने देते हुए बताया कि सम्मेलन में कम बच्चों के फायदे और परिवार नियोजन के साधनों को अपनाने की सलाह दी जाएगी। इन जिलों में सीमित परिवार को बढ़िया क्वालिटी के परिवार नियोजन के साधन और विकल्प भी उपलब्ध कराए जाएंगे। *(दै.न., 03.08.17)*

मिलेगा अच्छी गुणवत्ता का पोषाहार

छोटे बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं को अब अच्छी गुणवत्ता का पोषाहार मिलेगा। केंद्र सरकार ने पोषाहार की दरों में 25 से 45 फीसदी तक की बढ़ोतरी की है। पोषाहार की यह दरें प्रदेश में भी लागू होंगी। पोषाहार की दरें केंद्र सरकार ही तय करती है।

सरकार ने अगले तीन सालों में पोषाहार के लिए 9,900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट पास किया है। केंद्र सरकार ने 2011 के बाद पहली बार कीमतों में संशोधन किया है। वहीं किशोरियों को दिए जा रहे पोषाहार की कीमत 2010 के बाद पहली बार बढ़ाई है।

सरकार ने हर साल बिना किसी बाधा के दरें बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। प्रदेश में 60 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लाखों महिलाएं, बच्चे व किशोरियां पोषाहार ले रहे हैं। *(रा.प., 24.09.17)*

महिलाओं का बनेगा हैल्थ कार्ड

केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने महिलाओं में एनीमिया, ब्रेस्ट व सर्वाइकल कैंसर की बढ़ती समस्या के मद्देनजर हर साल महिलाओं का मुफ्त हैल्थ चेकअप कराने का निर्णय लिया है।

यह सुविधा पीएचसी से लेकर बड़े सरकारी अस्पतालों में मिलेगी। इसके तहत हर महिला को बच्चों के टीकाकरण की तरह हैल्थ कार्ड मिलेगा। इसे आधार कार्ड से लिंक करने पर निःशुल्क जांच होगी। योजना के तहत देश के हर राज्य की महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य की यह सुविधा मिलेगी। *(दै.भा., 17.07.17)*

महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी

मोदी सरकार 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए देश की नारी शक्ति की शरण में जाने वाली है। सरकार ने दशकों से लटके महिला आरक्षण बिल को संसद के अगले सत्र में पारित कराने की तैयारी शुरू की है।

इस बिल के पास होने से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके अलावा महिलाओं को साथ लाने के लिए कई कदम उठाने की तैयारी भी की जा रही है।

इस बिल को पुराने स्वरूप में ही लोकसभा में पेश किया जाएगा। सरकार की कोशिश होगी कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान यह बिल पेश हो जाए। *(रा.प., 20.09.17)*

तीन तलाक से आजाद हुई हमारी बेटियां

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने 1400 साल से चली आ रही तीन तलाक व तलाक-ए-बिद्दत की परंपरा को असंवैधानिक करार दे दिया है। पांच जजों की पीठ ने बहुमत से यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। तीन जजों ने कहा, तीन तलाक की प्रथा कुरान के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। कई इस्लामिक देशों में इस पर प्रतिबंध है तो क्या स्वतंत्र भारत इससे मुक्ति नहीं पा सकता?

यह फैसला एक झटके में वैवाहिक जीवन खत्म होने के भय में जी रही महिलाओं के लिए बड़ी राहत है। बेंच ने बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि तीन तलाक सहित कोई भी प्रथा जो कुरान के सिद्धांत से खिलाफ है, अस्वीकार है।

कोर्ट ने तीन तलाक को संविधान की धारा 14 और 21 के खिलाफ माना। पीड़ित महिला समेत 17 संगठनों की याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला आया है। यह फैसला न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि मुस्लिम महिलाओं के लिए स्वाभिमान पूर्वक जिंदगी जीने की एक शुरुआत भी है। *(रा.प., 23.08.17)*

वित्तीय सेवाएं

मनमर्जी के 'कंगालों' की संख्या बढ़ी...

बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेकर मनमर्जी से 'कंगाल' होने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इसके चलते वित्तवर्ष 2015-16 के मुकाबले मार्च में खत्म हुए वित्तवर्ष 2016-17 के दौरान मनमर्जी से कंगालों (विलफुल डिफॉल्टर्स) को दिए गए कर्ज में करीब 45 फीसदी का इजाफा हुआ है और उनको दिए गए कर्ज एक लाख करोड़ रुपए को भी पार कर गया है।

क्रेडिट सूचना ब्यूरो ट्रांसयूनियन सिविल के आंकड़ों के मुताबिक इस साल मार्च के अंत तक विलफुल डिफॉल्टर्स को दिया गया कर्ज 1 लाख 9 हजार 594 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। जबकि पिछले साल मार्च के अंत तक यह रकम 74 हजार 694 करोड़ रुपए थी। यानी सालभर के दौरान इसमें करीब 34 हजार 900 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले पांच सालों से विलफुल डिफॉल्टर्स की रकम में 84 हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

देश में सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को विलफुल डिफॉल्टर्स घोषित 997 कर्जदारों से 15,069 करोड़ रुपए वसूलने हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुल फंसे कर्ज का 27 प्रतिशत अकेले एसबीआई को वसूलना है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) विलफुल डिफॉल्टर्स से निपटने के लिए सख्ती से कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में कई डिफॉल्टर्स की संपत्ति जब्त भी हुई है। *(रा.प., 19.09.17)*

दूरसंचार सेवाएं

कम हुआ मोबाइल बिल का बोझ

बीते कई महीनों से टेलीकॉम सेक्टर में हलचल मची है। दरअसल रिलायंस जियो के आने से कई दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन जियो के आने से लोगों के काफी खर्चे बचे हैं। आम लोगों के मोबाइल बिल पिछले एक साल में 42 फीसदी तक कम हो गए हैं। पहले 1 जीबी डाटा के लिए 250 रुपए का खर्च करना पड़ता था वह अब घटकर 50 रुपए पर आ गया है।

इसके अलावा डोंगल, एसएमएस पैक, महंगी वीडियो कालिंग जैसे खर्चों में भी निजात मिला है। कुल मिला कर इस कंपनी ने पूरे इंडस्ट्री के काम-काज करने के तरीके में भी बदलाव ला दिया है। जिसका असर सिम एक्टीवेशन से डाटा ट्रांसफर तक में साफ दिखता है।

(रा.प., 06.09.17)

सड़क सुरक्षा

सड़क हादसों में मौतों के जिम्मेदार हम खुद!

सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने देश में सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों की ताजा रिपोर्ट जारी की है। आंकड़े काफी डराने वाले हैं। ड्राइविंग के दौरान की जाने वाली गलतियों... मसलन ओवर स्पीड, ओवर टेकिंग आदि से पिछले साल देश में डेढ़ लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है।

राजस्थान के संदर्भ में तो ये आंकड़े और भी चिंताजनक हैं। जो बताते है कि यहां 72 प्रतिशत हादसों में 74 प्रतिशत मौतों के जिम्मेदार हम खुद हैं। यानी ये मौतें ड्राइविंग लापरवाहियों से हुई हैं। सबसे ज्यादा 60 प्रतिशत मौतें ओवर स्पीड से हुई हैं, हर दूसरी मौत की वजह तेज गति है। शराब पीकर ड्राइविंग से 3 प्रतिशत लोग मारे गए।

देश में हुए कुल हादसों में राजस्थान का प्रतिशत 4.8 रहा है। 2016 में यहां 10 हजार 465 लोगों ने सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाई, 2015 में यह संख्या 10 हजार 510 थी। रिपोर्ट से यह भी सामने आया है कि प्रदेश में सड़क हादसों में हर घंटे किसी न किसी की मौत हो रही है, राज्य में प्रतिदिन मरने वालों का औसत 28 है। जयपुर और कोटा में हादसे बढ़े हैं जबकि जोधपुर में घटे हैं। *(रा.प., 08.09.17, 09.09.17)*

जन स्वास्थ्य

बिगड़ रहे हालात, विभाग बेफिक्र

प्रदेश में स्वाइन फ्लू व डेंगू के पांव पसारने, आए दिन बच्चों व महिलाओं की मौत होने, मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलने से दिनोंदिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले दिनों गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल में लापरवाही के चलते बांसवाड़ा में 53 दिन में 81 नवजात बच्चों की मौत हो गई ।

कहा जा रहा है कि पोषाहार नहीं मिलने से कमजोर बच्चे पैदा हो जाते हैं। यह स्थिति केवल बांसवाड़ा की ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में ऐसी स्थितियां सामने आती रही हैं। राज्यभर में तीन साल में पांच साल से कम उम्र के 52 हजार से भी ज्यादा बच्चे काल के ग्रास बन चुके हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों में तो डॉक्टर तो क्या, नर्सें तक मौजूद नहीं रहती। सरकारी अस्पतालों में उमड़ रहे मरीजों को निजी अस्पतालों में जाने को बाध्य किया जा रहा है। जच्चा-बच्चा सिर्फ राम हवाले है। प्रदेश मातृ व शिशु मृत्यु के मामले में बदनाम होता दिख रहा है। इन सब के बावजूद चिकित्सा विभाग बेफिक्र है। *(रा.प., 30 .08.17 एवं दै.भा., 08.09.17)*

पर्यावरण

प्रदूषण घटा लें तो बढ़ जाएगी जिंदगी

भारत में अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मानकों के साथ प्रदूषण को घटाने के निर्देशों को मानें तो चार साल ज्यादा जी सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में द एनर्जी पॉलिसी इन्स्टीट्यूट द्वारा विकसित एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स (एक्यूएलआई) में यह जानकारी दी गई है।

देश की राजधानी दिल्ली में अगर लोग डब्ल्यूएचओ मानकों का पालन करें तो लोग नौ साल ज्यादा जी सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता और मुंबई के रहने वाले निवासी लगभग 3.5 साल ज्यादा जी सकते हैं। पर इसके लिए जरूरी है कि डब्ल्यूएचओ मानकों के अनुसार पार्टिक्यूलेट मैटर (पीएम) के स्तर को स्वीकार कर लिया जाए। *(रा.प., 13.09.17)*

उपभोक्ता फैसले

दो इंच छोटा लहंगा देना, दिल्ली के शोरूम को पड़ा महंगा

दिल्ली की उपभोक्ता अदालत ने एक महिला की शादी में ऊंचा लहंगा सिलकर देने वाले एक बड़े फैशन डिजाइन स्टूडियो को न केवल लहंगे की कीमत के साथ 50 हजार रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया बल्कि पांच लाख रुपए राज्य के उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने की भी सजा दी है।

मामले की शुरुआत 2008 में हुई। महिला चांदनी चौक स्थित मशहूर शोरूम पर गई और अपनी शादी में पहनने के लिए मनपसंद लहंगा सिलने के लिए नाप दी। शादी के कुछ दिन पहले ट्रायल के लिए वह शोरूम गई तो लहंगे की लंबाई दो इंच कम निकली। साथ ही उसकी गोलाई भी सही नहीं थी। शोरूम संचालक ने कमियां दूर कर तय तारीख से पहले लहंगा पहुंचाने का वादा किया। लेकिन लहंगा शादी के दिन पहुंचा और उसमें दोनों कमियां ज्यों की त्यों थी।

शादी में उसे बेमन वह लहंगा पहनना पड़ा और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। शादी के बाद शोरूम संचालक ने लहंगे में दूसरा कपड़ा जोड़ कर उसे बेमेल कर दिया जो पहनने लायक भी नहीं रहा। हारकर महिला ने दिल्ली राज्य आयोग में परिवाद दायर किया। मुकदमा निपटने में आठ साल का लंबा समय लगा। लेकिन खुशी है, इस जागरूक महिला ने एक बड़ी जंग जीत ली। *(रा.प., 12.09.17)*

भारी पड़ा लोन चुकता होने पर भी घर के दस्तावेज नहीं लौटाना

जयपुर निवासी सुनील खंडेलवाल ने आईडीबीआई बैंक के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण मंच (द्वितीय) में परिवाद दर्ज कराया। अपने वकील के जरिए परिवाद में बताया गया कि उन्होंने वर्ष 2009 में आईडीबीआई बैंक से मकान के मूल दस्तावेज गिरवी रखकर होम लोन लिया था। उन्होंने बैंक से लिए गए होम लोन का ब्याज सहित पूरा भुगतान कर दिया। लेकिन लोन चुकता होने के बावजूद बैंक उन्हें मकान के मूल दस्तावेज नहीं लौटा रहा और दस्तावेज गुम होने की बात कह रहा है।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने बैंक द्वारा मूल दस्तावेज नहीं लौटाने को सेवा दोष माना और कहा कि बैंक द्वारा उपभोक्ता को मूल दस्तावेज वापस नहीं लौटा कर मानसिक पीड़ा पहुंचाई है। डुप्लीकेट कागजात मिलने पर भी उन्हें असल दस्तावेजों की कमी जीवन पर्यन्त खलती रहेगी। जेडीए से पट्टा जारी करवाते समय या भूखण्ड को बेचते समय समस्त कागजात देकर सामने वाले को सन्तुष्ट करना होगा। इससे हमेशा असुविधा बनी रहेगी।

मंच ने इस तथ्यों पर विचार करते हुए आईडीबीआई बैंक को आदेश दिए कि वह सुनील खंडेलवाल को 55,000 रुपए बतौर हर्जाना अदा करें। साथ ही उन्हें परिवाद व्यय के तौर पर अलग से 5,000 रुपए भी दिए जाएं। *(रा.प.एवं दै.न., 28.09.17)*

ग्रीन एक्शन वीक– 2017

सभी के लिए सतत् एवं सुरक्षित भोजन

जयपुर जिले में 'कट्स' संस्था द्वारा स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कन्जरवेशन के सहयोग से ग्रीन एक्शन वीक, 2017 सितम्बर-अक्टूबर में मनाया गया। इसके तहत जयपुर शहरी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर नुक्कड नाटक, स्कूल मीटिंग एवं कॉटेज मीटिंग के द्वारा महिलाओं, बच्चों एवं अन्य उपभोक्ताओं को जैविक पदार्थों के उपभोग के बारे में जानकारी दी। ग्रीन एक्शन वीक विश्व के 29 देशों में 53 संस्थाओं द्वारा मनाया गया। ग्रीन एक्शन वीक की इस बार की थीम सभी के लिए सतत् एवं सुरक्षित भोजन थी।

इसके अन्तर्गत जयपुर जिले में सौ किचन गार्डन विकसित करवाये गये जिसमें घर के अहाते में विभिन्न सब्जियों को उगाकर लोग अपनी दिनचर्या में उन सब्जियों को उपयोग में ले सकते हैं। इस वर्ष 'कट्स' संस्था के द्वारा ग्रीन एक्शन वीक जयपुर जिले के अलावा भारत के 12 राज्यों में विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से मनाया गया। जिसमें उपभोक्ताओं को सतत् एवं सुरक्षित भोजन के लिए जागरूक किया गया।

अवैध डिपॉजिट स्कीम तो होगी जेल

अगर कोई व्यक्ति अवैध डिपॉजिट स्कीम को प्रमोट करता है और उसके नाम पर लोगों से पैसे लेता है तो उसे 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा लोगों से जितने पैसे जमा किए, उसका दोगुना जुर्माना भी हो सकता है।

वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग इसके लिए नया बिल तैयार कर रहा है। जल्दी ही इसे केबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसका नाम 'बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स' रखा गया है। वित्त विभाग संसद के मानसून सत्र में इसे पेश करेगा।

(दै.भा., 12.07.17)

स्त्रोत: रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, डे.न्यू.: डेलीन्यूज

पाँचवा–स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोन: 91.141.513 3259 फैक्स: 228 2485, टेलीफैक्स: 401 5395, ई-मेल: cart@cuts.org, वेबसाईट: www.cuts-international.org के लिए जयपुर प्रिंटर्स प्रा. लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।